perquitites and improvement in service conditions. The demands are at negotiation stage between the FCI Management and the National Coordination Committee of the FCI Employees Union.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

(e) The additional D.A. and Interim Reliefs have already been allowed to the FCI employees.

Reservation for Backward Classes

774. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of WELFARE be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 2078 given in the Rajya Sabha on 13th March, 1987 and state:

(a) whether Government propose to evolve consensus on the question of reservation;

(b) if so, what are the steps taken in this regard; and

(c) if not, what are the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) to (c) The Government propose to have a national consensus evolved on the issue of reservation for Other Backward Classes. To help evolve the desired national consensus, modalities for eliciting public opinion on the list of Other Backward Classes prepared by the Mandal Commission are being worked out and a factual note on the position of reservation now obtaining in different States and Union Territories is being prepared on the basis of details collected from State Governments and Union Territories.

नई चीनी नीति के अन्तर्गत नई चीनी इकाइयों के लिए लाइसेंसों का दिया जाना

775. **श्री नरेश सो० पुगलिया:** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई चीनी नीति के अन्तर्गत, केवल उन्हीं चीनी इकाइयों को लाइसेंस दिए जायेंगे जिनकी न्यूनतम प्रारम्भिक क्षमता 2500 टी० सी० डी० होगी और क्या यही नीति पिछड़े क्षेत्रों पर भी लागू किए जाने की सम्भावना है ;

(ख) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि क्षमता बढ़ाने की यह नीति, जोकि 1200 टी०सी०डी० से बढ़ाकर 2500 टी० सी० डी० कर दी गई है, पिछड़े क्षेत्रों के हितों के विरुद्ध है ;

(ग) यदि कोई व्यक्ति सहकारी आधार पर पिछड़े क्षेत्रों में नई चीनी इकाइयां खोलना चाहे तो क्या ऐसी नई इकाइयों की क्षमता के पहलू पर सरकार पुनर्विचार करने का विचार रखती है ;

(घ) क्या सरकार सहकारी क्षेत्र में नई इकाइयां खोलने के लिए कुछ अन्य सुविधाएं देने का विचार रखती है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत): (क) जी, हां ।

(ख) पिछड़े क्षेत्रों में लगायी जाने वाली नयी चीनी फैक्ट्रियों की प्रारम्भिक क्षमता विषयक शर्त में ढील देने के बारे में केन्द्रीय सरकार के पास अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं ।

(घ) और (ङ) नयी लाइसेंसिंग नीति के अनुसार, सहकारी क्षेत्र में नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए अग्रता दी जा रही है । नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए सुविधाएं मुहैया करने हेतु कोई विशिष्ट योजनाएं नहीं हैं । सहकारी क्षेत्र में नये यूनिट स्थापित करने के लिए परियोजना की कुल लागत का 40 प्रतिशत राज्य

सरकार और उत्पादक सदस्यों के माध्यम से शेयर पूंजी के रूप में जुटाया जाना होगा। तथापि, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन०सी०डी०सी०) राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले शेयर पूंजी के अंशदान के एक भाग को प्रतिपूर्ति कर राज्य सरकारों की सहायता करता है। इन यूनिटों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा लेवी मुक्त चीनी के कोटे की अधिक प्रतिशतता आदि जैसे प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं।

Coconut as Oilseed

776. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that coconuts are not treated as "Oilseeds" though they yield coconut oil;

(b) if so, what are reasons therefor;

(c) whether Government are aware that due to this concept, the amount reserved for the Oilseeds Development during the seventh plan is not available to coconut growers; and

(d) if so what steps Government propose to take to include coconut in the item of oilseeds?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) and (b) Coconut is a perenniel plantation crop yielding edible oil.

(c) and (d) For coconut a statutory Board has been set up under an Act of Parliament and separate funds are provided for its development.

Against an allocation of Rs. 439.76 lakhs during the Sixth Plan a total sum of Rs. 900 lakhs is likely to be available during the Seventh Plan for coconut development programmes.

उत्तर प्रदेश में संयुक्त कृषि सहकारी समितियां

777. डा० रत्नाकर पाण्डेय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी संयुक्त कृषि सहकारी समितियां पंजीकृत की गयी हैं ;

(ख) इनमें सहकारी समितियां अभी भी सक्रिय हैं तथा लाभ में चल रही हैं; और

(ग) राज्य में संयुक्त कृषि सहकारी आंदोलन की दुःस्थिति के क्या कारण हैं तथा इसके निवारण के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (श्री जी० एस० डिल्लो): (क) और (ख) 30 जून, 1981 को उत्तर प्रदेश में 1332 संयुक्त कृषि सहकारी समितियां थीं, जिसके लिए जानकारी उपलब्ध है। इनमें से कार्य कर रही सहकारी समितियों की संख्या 634 थीं, जिसमें लाभ पर चलने वाली 377 समितियां शामिल हैं।

(ग) उत्तर प्रदेश के सातवीं पंचवर्षीय योजना के कागजात में सहकारी कृषि के संबंध में 4.85 लाख के परिव्यय से निम्नलिखित व्यवस्था की गई है :—

> सहकारी कृषि समितियों का सघन सर्वेक्षण शुरू किया गया है। यह प्रस्ताव किया गया है कि एकत्र जानकारी का विश्लेषण करने के बाद प्रमाणित बीजों के उत्पादन, आधुनिक कृषि उपस्करों के प्रयोग तथा परीक्षण, जिससे उत्पादन में वृद्धि, होगी के साथ कृषि कार्यक्रम का समन्वय करने के लिए विस्तृत योजनाएं बनाई जाएं।

Representation by Mini Steel Plants

778. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Gov-